शिमला से प्रकाशित

सरोकारी पत्रकारिता के लिए समर्पित

शैल

निष्पक्ष एवं निर्भीक साप्ताहिक समाचार

प्रकाशन का 48 वां वर्ष

ई-पेपर

www.facebook.com/shailsamachar

प्रदेश का पहला ऑनलाईन साप्ताहिक

वर्ष 48 अंक-33 पंजीकरण आरएनआई 26040/74 डाक पर्जीकरण एच. पी./93/एस एम एल Valid upto 31-12-2023 सोमवार 14-21 अगस्त 2023 मूल्य पांच रूपये

पत्र बम्बों के छींटे मुख्यमंत्री कार्यालय तक आना शुभ संकेत नहीं हैं

- यह दूसरा पत्र कहीं सीबीआई जांच की कड़ी तो नहीं
- लोकसभा चुनाव के परिदृश्य में घातक है इन पत्रों का आना

शिमला/शैल। सुक्खू सरकार के आठ माह के कार्यकाल में पावर कॉरपोरेशन की कार्य प्रणाली को लेकर दूसरा पत्र वायरल होकर चर्चा में आ गया है। यह पत्र सी.बी.आई. निदेशक के नाम लिखा गया है। पत्र में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाये गये हैं। आरोपों की छाया मुख्यमंत्री तक आ रही है। पत्र लिखने वाले ने अपना नाम अनमोल सिंह ठाकुर बताते हुये स्वयं को इसी कॉरपोरेशन का सहायक प्रबंधक होने का दावा किया है। भ्रष्टाचार का आकार सैकड़ों करोड़ का कहा गया है। अपने आरोपों के साक्ष्य के रूप में इस पत्र के साथ 38 पन्नों के दस्तावेज भी संलग्न करने का दावा है। यह आरोप लगाने वाला अनमोल सिंह इसी कॉरपोरेशन का सहायक प्रबंधक है या नहीं इसकी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन इसको लेकर कॉरपोरेशन या सरकार की ओर से कोई अधिकारिक खंडन भी जारी नहीं हुआ है। लेकिन कॉरपोरेशन के सूत्रों का यह भी दावा है कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। जब इसी कॉरपोरेशन को लेकर पहला पत्र बम्ब जारी हुआ था तब यह कहा गया था कि पत्र और उसमें दर्ज आरोपों की प्रमाणिकता सत्यापित करने के निर्देश जारी किये गये हैं। लेकिन इन निर्देशों का परिणाम क्या रहा है यह अब तक सामने नहीं आया है। वह पत्र प्रधानमंत्री को भेजा गया था और आरोपों पर सी.बी.आई. जांच की मांग की गयी थी। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने भी उस पत्र को सी.बी.आई. को सौंपने की मांग की थी। तब इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा था कि जयराम जिससे चाहे जांच करवा लें। वह पत्र प्रधानमंत्री कार्यालय से होकर सी.बी.आई. तक पहुंच गया था। क्योंकि पटेल इंजीनियरिंग कंपनी जम्मू-कश्मीर के प्रोजेक्ट के संदर्भ में पहले से ही सी.बी.आई. के राडार पर चल रही है। हिमाचल पॉवर कॉरपोरेशन भी आई.डी.बी.आई. आदि बैंकों के माध्यम से धन का जुगाड़ कर रही है। इन ऋणों के लिए केंद्र सरकार की गारन्टी रहती है। 90:10 के अनुपात में मिलने वाले इन ऋणों के कारण केंद्रीय एजैन्सी सी.बी.आई. का दखल भी इस मामले पर बन जाता है। पावर कॉरपोरेशन को कुछ और जल विद्युत परियोजनाओं के निष्पादन का काम भी सरकार ने सौंप रखा है। इस परिदृश्य में यदि वर्तमान पत्र को देखा जाये तो यह भी संकेत उभरता है कि कहीं सी.बी.आई. ने पावर कॉरपोरेशन से कोई रिकॉर्ड तो तलब नहीं कर लिया है। कुछ सूत्रों का यह भी दावा है कि यह पत्र उसी कड़ी में है। इन पत्रों की जांच हो पाती है या नहीं? उस जांच का परिणाम क्या रहता है? क्या इन पत्रों और इन पर उठी जांच की मांग का कोई संबंध आने वाले लोकसभा चुनावों से भी निकलता है या नहीं यह तो आने वाला समय ही बतायेगा। लेकिन कॉरपोरेशन को लेकर आये दोनों पत्रों की आंच का मुख्यमंत्री कार्यालय तक पहुंचना इसका निश्चित संकेत है कि मुख्यमंत्री को घेरने के लिए एक पुख्ता योजना पर काम हो रहा है। विश्लेषकों का मानना है कि मुख्यमंत्री के अपने खिलाफ जो FIR का मामला अदालत में लंबित चल रहा है वह भी चुनावों में एक विषय बनेगा। इस परिदृश्य में लोकसभा चुनावों तक जो राजनीतिक घटनाक्रम उभरता नजर आ रहा है उसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। क्योंकि लोकसभा जीतने के लिए भाजपा किसी भी हद तक जा सकती है। इन पत्रों में मुख्यमंत्री के अपने कार्यालय पर छींटें आना और मुख्यमंत्री द्वारा कोई कारवाई न कर पाना अपने में बहुत कुछ कह जाता है।

यह है पत्र

To,

Mr. Praveen Sood,

Director

Central Bureau of Investigation

Plot No. 5-B,CGO Complaex, Lodhi Road

New Delhi, Pin- 110003.

Dear Sir,

them in getting some of the ...

His all visit to Chandigarh should be investigated in details as he goes to collect money from havala operator.(two of Hotel entries and restaurant bills are attached for investigation).I request you for very strong necessary action.

Total Enclosure – 38 Pages

Yours Sincerely

Anmol Singh Thakur,

Assistant Manager, HPPCL ,

Shimla (HP).

आपदा की इस घड़ी में राजनीति छोड़ मदद पर ध्यान दे कांग्रेस:अनुराग ठाकुर

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने से हो रही भारी तबाही व जान-माल के नुकसान पर को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण व दुखद बताते हुए केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण और युवा एवं खेल मामलों के मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस को इस पर राजनीति न करने का आग्रह किया। ठाकुर ने कहा मेरा सभी राजनीतिक दलों खासकर कांग्रेस से आग्रह है कि संकट की इस घड़ी में राजनीति बंद करें और राहत कार्यों में ज्यादा से ज्यादा मदद करें।

बिहार के लोगों के ऊपर टिप्पणी को दुर्भाग्यपूर्ण व अकारण बताते हुए ठाकुर ने कहा आपदा के समय हमें आपस में मिलकर काम करना चाहिए। टीका टिप्पणी करने से काम नहीं चलेगा। बिहार के लोगों को बिना कारण इसमें घसीटना और उन को अपमानित करना ठीक नहीं है।'

ठाकुर ने सभी राजनीतिक दलों व सामाजिक संगठनों को राहत और बचाव कार्य में एक साथ आने का आवाहन करते हुए कहा, 'हम सभी मिलकर एक दूसरे की मदद करें। मेरा हिमाचल के मंत्रीगणों से भी आग्रह है कि अलग-अलग भाषा और अलग-अलग सुर में बोलने से बचें और राहत कार्य पर ध्यान लगाएं।

केंद्र द्वारा राहत व बचाव कार्य में मदद की जानकारी देते हुये ठाकुर ने कहा, 'केंद्र सरकार सभी प्रकार से राज्य सरकार के साथ समन्वय बिठाकर कार्य कर रही है। हम लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। राहत के लिए एनडीआरएफ की टुकड़ियां हिमाचल में हैं। वायु सेना लगातार आपदा प्रभावित क्षेत्रों से लोगों को बाहर निकल रही है। पिछले 72 घंटे में 1000 से ज्यादा लोगों को सकुशल निकाला गया है।

आगामी 20 और 21 अगस्त को अपने हिमाचल दौरे की जानकारी देते हुए हमीरपुर सांसद ने बताया की वह अलग-अलग जिलों में घूम कर सभी शोकाकुल परिवारों से मिलेंगे जिन्होंने इस आपदा में अपने स्वजन खोये हैं। ठाकुर ने कहा, हम सभी अधिकारियों से अभी भी संपर्क में हैं। हिमाचल पहुंच कर भी उनके साथ मिल बैठकर राहत व बचाव कार्य में और तेजी कैसे लाई जाए इस पर कार्य करेंगे।

आम लोगों के लिए खुला राजभवन

शिमला/शैल। हिमाचल प्रदेश राजभवन आम जनता के लिए खोल दिया गया है। पहले दिन स्थानीय स्कूल के 60 बच्चों ने राजभवन का भ्रमण किया। उन्होंने इस धरोहर भवन का भ्रमण कर यहां संरक्षित समृद्ध संस्कृति का जायजा लिया और

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से अपने अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर राजभवन के इतिहास पर आधारित एक लघु वृत्तचित्र भी प्रदर्शित किया गया। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल तथा लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल ने राजभवन के दरबार हाल में बड़ी संख्या में लोगों और बच्चों के साथ यह वृतचित्र देखा।

मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि राजभवन एक ऐतिहासिक धरोहर है और इसे आम आदमी के लिए खोलने के निर्णय से यहां फिर से चहल-पहल कायम करने का प्रयास किया गया है ताकि हर आम व खास इस धरोहर एवं यहां की विरासत से प्रत्यक्ष रूप से रू-ब-रू हो सकें। उन्होंने कहा कि सभी के सहयोग से ही यह संभव हो पाया है और उन्हें विश्वास है कि उनके निर्णय से हर कोई सहमत होगा। उन्होंने कहा कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की पहल पर शिमला में राष्ट्रपति निवास आम जनता के लिए खोला गया है और इसी तर्ज पर राजभवन खोलने का भी निर्णय लिया गया है।

शिव प्रताप शुक्ल ने कहा कि उन्हें राज्यपाल बनने के बाद ही पहली बार शिमला आने का अवसर प्राप्त हुआ है, हालांकि वे इसके ऐतिहासिक महत्व से पहले से ही भलीभांति परिचित रहे हैं। इसी तरह पर्यटक, दूसरे राज्यों से आने वाले अन्य लोग और स्थानीय जनता भी राजभवन के इतिहास से वाकिफ तो हैं, लेकिन प्रोटोकॉल के कारण वे इसे भीतर से निहार पाने एवं इसके अवलोकन से वंचित रह जाते थे। राजभवन को खोलने के निर्णय से अब वे हिमाचल प्रदेश के इस ऐतिहासिक भवन की भव्यता, समृद्धि और परम्पराओं को भलीभांति देख व समझ पाएंगे। राजभवन में शिमला एग्रीमेंट टेबल सहित स्वतंत्रता पूर्व की अनेक बहुमूल्य कलाकृतियां संरक्षित की गई हैं, जिनका वे अब अवलोकन कर सकते हैं।

राजभवन के प्रवक्ता ने बताया कि राजभवन का भ्रमण करने के लिए व्हाट्सएप नंबर 94183-16617 और लैंडलाइन 0177-2624152 पर संपर्क कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त ईमेल:visit.rajbhavan @gmail.com पर भी आवेदन किया जा सकता है।

राज्यपाल ने राजभवन में राष्ट्रीय ध्वज फहराया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के

अवसर पर राजभवन परिसर में राष्ट्रीय ध्वज फहराया। लेडी गवर्नर जानकी शुक्ल भी इस मौके पर उपस्थित रहीं।

राज्यपाल ने प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की बधाई देते हुए उनके सुखमय एवं समृद्ध जीवन की कामना की। उन्होंने कहा कि यह एक ऐतिहासिक दिन है जब देश को विदेशी साम्राज्य की बेड़ियों से आजादी मिली। उन्होंने कहा कि असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और वीर सपूतों के संघर्ष ने हमें आजादी दिलाई है।

शुक्ल ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस पर, हम उन सभी देशभक्तों और वीर सपूतों को भी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने आजादी के बाद देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने और देश की सीमाओं की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया है।

उन्होंने प्रदेश की प्रगति एवं सर्वांगीण विकास की कामना करते हुए कहा कि हम सभी को संकल्प लेना चाहिए कि हम और अधिक समर्पण एवं प्रतिबद्धता के साथ देश एवं प्रदेश की प्रगति के लिए अपने कर्तव्य का निर्वहन करेंगे।

इस अवसर पर राज्यपाल ने राजभवन कर्मियों को राष्ट्रीय ध्वज भी प्रदान किए।।

इस मौके पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने राहत सामग्री वाहनों को रवाना किया

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने राज भवन से राज्य रेडक्रॉस की ओर से कुल्लू, हमीरपुर और कांगड़ा ज़िला की रेडक्रॉस शाखाओं के लिए तीन राहत सामग्री वाहनों को रवाना किया।

इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि इस प्राकृतिक आपदा के समय राज्य रेडक्रॉस प्रभावित परिवारों को राहत पहुंचाने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राहत सामग्री में कंबल, तिरपाल, टेंट तथा स्वच्छता किट इत्यादि शामिल है। उन्होंने कहा कि इस संकट की घड़ी में समस्त प्रदेश की जनता प्रभावितों के साथ है और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए एकजुट प्रयास कर रही है।

उन्होंने प्रदेशवासियों से प्रभावितों की सहायता के लिए अधिक से अधिक योगदान करने का भी आग्रह किया।

इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

राज्यपाल ने कृष्णा नगर के प्रभावितों को राहत सामग्री वितरित की

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने शिमला के कृष्णा नगर का दौरा कर, भू-स्खलन के कारण प्रभावित हुए परिवारों से भेंट की। प्रभावितों को रहने के लिए सामुदायिक हाल में वैकल्पिक स्थान प्रदान किया गया है। उन्होंने प्रभावितों के साथ संवाद भी किया। राज्यपाल ने प्रभावितों को राज्य रेडक्रॉस के माध्यम से राहत सामग्री भी वितरित

की। इस अवसर पर लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह और राष्ट्रीय रेडक्रॉस प्रबंधन समिति की सदस्य डॉ. साधना ठाकुर भी उपस्थित थीं।

प्रदेश सहित शिमला शहर में लगातार हो रही भारी बारिश के दौरान कई जगहों पर भू-स्खलन के कारण जान-माल की क्षति हुई है। शहर के कृष्णा नगर में कई मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं और कुछ अन्य खतरे की जद में हैं। इस अवसर पर स्थानीय निवासियों द्वारा राज्यपाल को अवगत करवाया गया कि यहां पर लगभग 250 से 300 परिवार प्रभावित हुए हैं। शुक्ल ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में हर व्यक्ति को मदद के लिए आगे आना चाहिए। राज्य सरकार हर स्तर पर प्रभावितों को राहत पहुंचा रही है।

उन्होंने जिला प्रशासन को घरों के लिए खतरा बने पेड़ों को हटाने की व्यवस्था करने के निर्देश दिए। इसके अलावा, उन्होंने यहां रहने वाले प्रभावित परिवारों के लिए बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने प्रभावित परिवारों को हरसंभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया।

प्रदेश में नई सड़क परियोजनाओं की निगरानी के लिए उच्च स्तरीय समिति गठित की जाएगी: मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में बनने वाली सभी सड़कों में ड्रेनेज और

क्रॉस ड्रेनेज बनाना अनिवार्य किया जाएगा। इसकी निगरानी के लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी और निगरानी टीमें भी गठित की जाएंगी। यहां आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्रेनेज और क्रॉस ड्रेनेज न होने के कारण सड़कें क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। उन्होंने कहा कि जिन सड़कों में निर्माण के समय ड्रेनेज नहीं होगी, उन्हें पास भी नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण के समय ही गुणवत्तापूर्ण कार्य से सड़कों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। उन्होंने प्रदेश में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट लेकर अधिकारियों को जरूरी दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बाधित सड़कों को 24 घंटे कार्य कर बहाल किया जाए।

मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को भूस्खलन से क्षतिग्रस्त सड़कों को खोलने के लिए भारी मशीनरी और उपकरणों का उपयोग सुनिश्चित करने को भी कहा। उन्होंने कहा कि जिला मंडी में बाधित प्रमुख सड़कों को खोलने के लिए अतिरिक्त कार्य बल और मशीनरी की आवश्यकता है। सड़कें पहाड़ की जीवन रेखाएं हैं और इन्हें सुचारू बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुल्लू में नदी किनारों पर पानी से भूमि कटाव को रोकने के लिए वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन सुनिश्चित किया जाएगा। इसके दृष्टिगत राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और लोक निर्माण विभाग को दूरगामी उपाय करने को कहा गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने राज्य में राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल की कंपनियों को दो-दो क्रेन उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया है, इससे आपदा प्रबंधन और बचाव कार्यों को तीव्रता से करने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि सभी जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को ड्रोन भी उपलब्ध करवाए जाएंगे, इससे मैपिंग व निगरानी के साथ-साथ आपदा के समय लोगों को सामान व चिकित्सा सहायता उपलब्ध करवाने में मदद मिलेगी। बैठक में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, मुख्यमंत्री के ओएसडी गोपाल शर्मा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, प्रधान सचिव ओंकार शर्मा, भरत खेड़ा व देवेश कुमार, विभिन्न विभागों के सचिव और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

शैल समाचार
संपादक मण्डल
संपादक- बलदेव शर्मा
सयुक्त संपादक:जे.पी.भारद्वाज
विधि सलाहकार: ऋचा शर्मा

राज्य रेडक्रॉस के लिए अंशदान

शिमला/शैल। राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल को राजभवन में राज्य रेडक्रॉस की मानद सचिव डॉ. किमी सूद और आशा

शर्मा, मोनिता, कीर्ति और मोनिका सहित अन्य सदस्यों ने 26 हजार रुपये रुपये का चेक भेंट किया गया। इस राशि का उपयोग रेडक्रॉस के माध्यम से पीड़ित मानवता की सेवा में किया जाएगा। राज्यपाल राज्य रेडक्रॉस सोसाइटी के अध्यक्ष भी हैं।

राज्यपाल ने सभी सदस्यों का इस अमूल्य योगदान के लिए आभार व्यक्त किया और लोगों से जरूरतमंदों की मदद के लिए आगे आने का आग्रह भी किया। इस अवसर पर राज्यपाल के सचिव राजेश शर्मा भी उपस्थित थे।

मुख्यमंत्री ने शिमला के रिज पर राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह की अध्यक्षता की

शिमला/शैल। स्वतंत्रता दिवस का राज्य स्तरीय समारोह ऐतिहासिक रिज मैदान, शिमला में आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और मार्च पास्ट की सलामी ली। परेड में पुलिस, होमगार्ड, एनसीसी, एनएसएस, स्काउट्स एंड गाइड की टुकड़ियां शामिल हुई, जिसका नेतृत्व पुलिस उप-अधीक्षक प्रणव चौहान ने किया।

भारी बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश में आई आपदा के बीच प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सादगी के साथ आयोजित किए गए। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित नहीं हुए।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने लोगों को सम्बोधित करते हुए स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी और कहा कि हिमाचल प्रदेश के लोगों के लिए जश्न मनाने का यह सही समय नहीं है। उन्होंने कहा कि पिछले दो दिनों में प्रदेश पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा है। कई स्थानों पर बादल फटने और पहाड़

खिसकने की प्रलयंकारी घटनाएं सामने आई हैं। लोगों द्वारा तिनका-तिनका जोड़कर बनाए गए घर इस आपदा के दौरान मलबे में दब गए हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं और रोते बिलखते लोगों को देखकर उनका मन अत्यंत दुखी है। उन्होंने कहा कि पिछले चौबीस घंटे में हमने 50 बहुमूल्य जीवन खोये हैं। हिमाचल प्रदेश में मानसून आने के बाद से 300 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। उन्होंने इस अवसर पर सभी मृतकों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रभावित परिवारों के लिए यह मुश्किल की घड़ी है लेकिन राज्य सरकार, प्रदेश के लोगों के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है। उन्होंने कहा कि प्रभावितों के घाव पैसे से नहीं भरे जा सकते हैं, लेकिन राज्य सरकार एक-एक पैसा जोड़ कर सभी प्रभावितों का घर बसायेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि त्रासदी को देखते हुए इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम सेरेमोनियल रूप से मनाये जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा से भारी तबाही हो रही है तथा यह पिछले 50 साल की सबसे बड़ी आपदा है। जगह-जगह घर और सड़कें टूट रही हैं। किसानों के खेत व फसलें तबाह हो रही हैं और पूरे प्रदेश में आपदा से भारी नुकसान हो रहा है। इस त्रासदी का हिमाचल प्रदेश के सभी लोग बड़ी मजबूती के साथ सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल जैसे छोटे से राज्य में 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक के नुकसान का अनुमान है। आर्थिक बदहाली के दौर से गुजर रहे हिमाचल को राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए केन्द्र सरकार से आर्थिक मदद की जरूरत है। मुख्यमंत्री ने उम्मीद व्यक्त की कि जल्द ही केन्द्र सरकार प्रदेश को अंतरिम राहत की पहली किस्त जारी करेगी।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि विधवाओं के लिए प्रदेश सरकार ने मुख्यमन्त्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना शुरू की है। इसके तहत इस वर्ष, 7 हजार ऐसी महिलाओं को मकान बनाने के लिए, प्रति महिला डेढ़ लाख रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानियों को प्रदेश सरकार की ओर से दी जाने वाली सम्मान राशि को 15000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 25000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की तथा जिन स्वतंत्रता सेनानियों की मृत्यु हो चुकी है, उनकी पत्नियों को प्रदेश सरकार द्वारा दी जा रही सम्मान राशि को भी 15,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 20,000 रुपये प्रतिमाह करने की घोषणा की। उन्होंने शत्रु सेना के विरुद्ध सैन्य अभियान के दौरान युद्ध के दौरान शहीद होने अथवा घायल या गुम होने वाले सैनिकों के आश्रितों को प्रदेश सरकार द्वारा अनुग्रह अनुदान राशि में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि युद्ध या यद्ध जैसी परिस्थितियों में शहीद सैनिक के आश्रितों को 20 लाख रुपये के स्थान पर अब 30 लाख रुपये प्रदान किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि नॉन ऑपरेशनल क्षेत्रों में अथवा ऐसे ऑपरेशनल क्षेत्रों, जहां युद्ध न हो, में शहीद होने वाले सैनिक के आश्रितों को 5 लाख रुपये के स्थान पर अब 7 लाख 50 हजार रुपये दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सैन्य अभियान के दौरान 50 प्रतिशत से अधिक अपंगता वाले सैनिकों को 3.75 लाख रुपये तथा 50 प्रतिशत से कम की अपंगता वाले सैनिकों को 1.50 लाख रुपये प्रदान किए जाएंगे।

मुख्यमंत्री ने विधवा पुनर्विवाह योजना के अन्तर्गत दी जानी वाली सहायता राशि को 65 हजार रुपये को बढ़ाकर 2 लाख रुपये करने की घोषणा भी की। उन्होंने मनरेगा मजदूरों की दिहाड़ी को सामान्य क्षेत्र में 224 से 240 रुपये तथा जनजातीय क्षेत्र में 280 से 294 रुपये करने की घोषणा की। इस घोषणा से मनरेगा में काम करने वाले 9 लाख परिवार लाभान्वित होंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार पूरक पोषण के रूप में गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं तथा 6 माह से 6 वर्ष के बच्चों व कुपोषित बच्चों के पोषण व स्वास्थ्य सम्बंधी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना को आरम्भ करने की घोषणा करते हुए कहा कि इस योजना के लिए 50 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया जाएगा, जिसमें स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों में शिशु और माता के स्वास्थ्य को प्राथमिकता दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि आपदा में बागवानों को काफी नुकसान पहुँचा है, जिसे उन्होंने स्वयं देखा है। उन्होंने सेब, आम और लीची फलों के लिए मण्डी मध्यस्थता योजना के तहत समर्थन मूल्य में वर्ष 2023 में बढ़ौतरी की घोषणा की। उन्होंने सेब के समर्थन मूल्य में ऐतिहासिक डेढ़ रूपये की बढ़ौतरी कर इसे 10.50 रुपये से बढ़ाकर 12 रुपये करने की भी घोषणा की।

बाढ़ विस्थापितों का पुनर्वास प्रदेश सरकार की प्राथमिकता:मुख्यमंत्री

पावंटा-शिलाई राजमार्ग के स्थाई समाधान को कच्ची ढांक में पुल निर्माण की घोषणा

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सिरमौर जिला के तीन विधानसभा क्षेत्रों पावंटा साहिब, शिलाई तथा नाहन के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया और प्रभावित लोगों से संवाद किया। उन्होंने कहा कि इस बार की बरसात प्रदेश के हजारों परिवारों को गहरे घाव दे गई है और प्रदेश सरकार प्रभावितों की हरसंभव मदद के लिए प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने बादल फटने की घटना, बाढ़ व भूस्खलन के कारण प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का निरीक्षण कर वहां हुई क्षति का जायज़ा लिया। मुख्यमंत्री ने शिलाई विधानसभा क्षेत्र के अंबौण में गत दिनों भारी बाढ़ की चपेट में आये 22 मकानों के प्रभावित प्रत्येक परिवार को एक-एक लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन परिवारों की फसलें खराब हुई हैं, प्रदेश सरकार उन्हें भी उपयुक्त मुआवज़ा प्रदान करेगी। बरसात में अपने आशियाने तथा खेत-खलियान पूरी तरह से खो चुके परिवारों के पुनर्वास को प्राथमिकता प्रदान की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस संबंध में व्यापक चर्चा के उपरांत एक नीति बनाई जाएगी ताकि सरकार अपने संसाधनों से ही प्रभावित परिवारों के पुनर्वास की व्यवस्था कर सके। उन्होंने कहा कि पावंटा-शिलाई राष्ट्रीय राजमार्ग के कच्ची ढांक में एक बड़े पुल का निर्माण किया जाएगा जिससे राजमार्ग पर बार-बार मलबा गिरने से यातायात बाधित होने की समस्या का स्थायी समाधान सुनिश्चित हो सकेगा।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि अभी तक प्रदेश में निजी व सरकारी संपत्ति को लगभग 10 हजार करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है और इसकी भरपाई में समय लगेगा। उन्होंने दोहराया कि प्रदेश सरकार संकट की इस घड़ी में प्रत्येक प्रभावित के साथ है। उन्होंने आश्वस्त किया कि क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवज़े के साथ ही जिन मकानों में सिल्ट आई है, उन्हें भी आर्थिक मदद उपलब्ध करवाई जाएगी। उन्होंने कहा कि पशुधन की मौत पर बढ़े हुए मुआवज़े का भी प्रावधान किया गया है।

आपदा में अपने परिवार को खो चुके विनोद कुमार को सांत्वना देने मुख्यमंत्री उनके घर पहुंचे। सिरमौरी ताल में आई भयंकर बाढ़ के कारण विनोद का परिवार मकान सहित दब गया था और इसमें 5 लोगों की मौत हो गई थी। उन्होंने विनोद कुमार व अन्य परिजनों को 20 लाख रुपये की आर्थिक सहायता के चेक भी प्रदान किए। मुख्यमंत्री ने राहत शिविर में पहुंचकर सिरमौरी ताल में बेघर हुए 17 परिवारों से भी संवाद किया और प्रशासन को इन परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री नाहन विधानसभा क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र कंडईवाला भी पहुंचे। इस क्षेत्र में लगभग डेढ़ किलोमीटर क्षेत्र बादल फटने के कारण आई बाढ़ से प्रभावित हुआ है जिसमें मकानों समेत लोगों की फसलों को भी भारी नुकसान पहुंचा है। मुख्यमंत्री ने लोक निर्माण विभाग को सड़क के दोनों ओर से मलबा तुरंत हटाने तथा सड़क में कलवर्ट और नालियां बनाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्रे बाढ़ में बहने से मृत्यु को प्राप्त इमरान तथा बिंदरो देवी के परिजनों से भी मिले और दोनों के परिवारों को 3.75 लाख रुपये प्रत्येक के चेक प्रदान किए।

उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने मुख्यमंत्री को अवगत करवाया कि सिरमौर जिला में प्राकृतिक आपदा से अभी तक कुल 372 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। इसमें 21 लोग काल का ग्रास बने और 22 लोग घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि 40 मकान मलबे में दबकर तबाह हो गए जबकि 35 पशुधन की मौत हुई है। उन्होंने कहा कि बहाली कार्यों के लिए लोक निर्माण, विद्युत व जल शक्ति विभाग को लगभग 10 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई है। उन्होंने जिला के लिए उदारतापूर्वक धनराशि उपलब्ध करवाने तथा राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री का आभार भी व्यक्त किया।

विधायक विनय कुमार, अजय सोलंकी व सुखराम चौधरी, पूर्व विधायक किरनेश जंग, विभिन्न विभागों के अधिकारियों सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मुख्यमंत्री के साथ मौजूद रहे।

विधायक क्षेत्र विकास निधि में सुरक्षा दीवार एवं तटीयकरण के कार्य शामिलः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए 'विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना' के तहत नियमों में छूट देकर इस योजना के तहत सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीयकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। हाल ही में वर्षा के कारण प्रदेशभर में भारी जान-माल के नुकसान के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। उन्होंने बताया कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने-अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के चलते प्रदेश को आपदा का सामना करना पड़ रहा है जिस कारण राज्यभर में बहुमूल्य जाने गई हैं और निजी एवं सरकारी सम्पत्ति को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया कि सरकार बाधित सड़कों और जलापूर्ति योजनाओं की बहाली के लिए दिन-रात कार्य कर रही है। इसके अलावा आपदा से प्रभावित परिवारों को हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए भी प्रदेश सरकार प्रतिबद्ध है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत एवं बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत यह निर्णय लिया गया है। सुरक्षा दीवारों व ब्रेस्टवॉल इत्यादि के संरक्षण और नालों के तटीयकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी अथवा ग्राम पंचायत प्रधान की ओर से जून, 2023 के पश्चात बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाण-पत्र उपलब्ध करवाना होगा।

बारिश के कारण भू-क्षरण की संभावनाएं बढ़ने और निजी एवं सामुदायिक सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए नाले का रख-रखाव अति आवश्यक होने संबंधी पटवारी एवं प्रधान द्वारा दिए गए प्रमाण-पत्र के आधार पर संबंधित क्षेत्र के विधायक नालों के तटीयकरण के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत सिफारिश कर सकेंगे।

बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत हिमाचल 'प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र' घोषितः मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश में भारी बारिश से हुए नुकसान के दृष्टिगत राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश को 'प्राकृतिक आपदा प्रभावित क्षेत्र' घोषित किया है। उन्होंने कहा कि विगत दिनों से जारी भारी बारिश, बादल फटने और भूस्खलन की घटनाओं से प्रदेश में जान-माल का भारी नुकसान हुआ है। राज्य में पेयजल, विद्युत आपूर्ति व्यवस्था व सड़कों सहित अन्य संसाधनों को भी भारी क्षति पहुंची है। अभी तक राज्य में 12 हजार से अधिक घर क्षतिग्रस्त हुए हैं और 330 लोगों की बहुमूल्य जान चली गई हैं। प्रदेश में अभी तक 10 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का नुकसान आंका गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कृषि और बागवानी को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि राज्य में संचार व्यवस्था पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। राज्य में जन-जीवन अस्त-व्यस्त हुआ है और व्यावसायिक गतिविधियां भी आपदा से अछूती नहीं रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश के कई क्षेत्रों में लोगों को राहत शिविरों में शरण लेनी पड़ी है। खतरे के दृष्टिगत बहुत से लोगों को उनके घरों से सुरक्षित निकालकर दूसरे स्थानों पर पहुंचाया गया है।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार राहत, बचाव एवं पुनर्वास के लिए युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है। आपदा प्रभावितों को हरसंभव मदद सुनिश्चित की जा रही है।

उन्होंने कहा कि मौसम के अनुकूल होने पर सम्बन्धित जिलों और विभागों द्वारा सम्पत्ति, पशुधन, आधारभूत संरचना और अन्य नुकसान का आकलन कर पुनर्निर्माण और उपयुक्त कारवाई के लिए प्रदेश सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने केन्द्र सरकार से आपदा की इस घड़ी में प्रदेश को दिल खोलकर सहायता प्रदान करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में जन-जीवन को पटरी पर लाते हुए सामान्य व्यवस्था बनाने संबंधी गतिविधियों में और तेजी लाई जा सके।

इच्छा का समुद्र हमेशा अतृप्त रहता है । उसकी माँगे ज्यों – ज्यों पूरी की जाती है, त्यों – त्यों और गर्जन करता है।

..... स्वामी विवेकानंद

सम्पादकीय

क्या अब राजधानी बदलने का वक्त आ गया है

इस मानसून में जिस तरह की तबाही पूरे प्रदेश में देखने को मिली है उससे कुछ ऐसे बुनियादी सवाल उठ खड़े हुये हैं जिन्हें भविष्य को सामने रखते हुए नजरअंदाज करना संभव नहीं होगा। यह तबाही प्रदेश के हर जिले में हुई है और इसके बाद प्रदेश को लेकर अब तक हुये सारे भूगर्भीय अध्ययन भी चर्चा में आ खड़े हुये हैं। इन सारे अध्ययनों में यह कहा गया है की पूरा प्रदेश भूकंप क्षेत्र में आता है। एक वर्ष में ऊना को छोड़कर अन्य सभी जिलों में हुये 87 भूकंपों का आंकड़ा सामने आ चुका है। इन भूकंपो से भूस्खलन, पहाड़ों में लैंडस्लाइड, बाढ़ आदि होना यह अध्ययनों में आ चुका है। इसका कारण पहाड़ों में बनी जल विद्युत परियोजनाओं और यहां बनाई गई सड़कों को कहा गया है। इन जल विद्युत परियोजनाओं और सड़कों के निर्माण से पर्यटन का विकास हुआ। यह सारा विकास पिछले तीन दशकों की जमा पूंजी है। इस सारे विकास से जो आर्थिक लाभ प्रदेश को पहुंचा है उसी का परिणाम है प्रदेश पर खड़ा एक लाख करोड़ के करीब का कर्ज और इतना ही इसके लिये दिया गया उपदान। लेकिन इतनी कीमत चुकाकर खड़ा किया गया यह विकास कितनी देर टिक पायेगा।

1971 में किन्नौर में आये भूकंप का असर शिमला के रिज और लक्कड़ बाजार क्षेत्र में आज भी देखा जा सकता है। आज तक रिज अपने पुराने मूल रूप में नहीं आ सका है। हर वर्ष रिज के जख्म हरे हो जाते हैं। इसी विनाश के कारण 1979 में यह माना गया कि प्रदेश के सुनियोजित विकास के लिए नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग चाहिए और परिणामतय: टीसीपी विभाग का गठन हुआ। प्रदेश के नगरीय और ग्रामीण विकास के लिये एक स्थाई विकास योजना तैयार करने की जिम्मेदारी इस विभाग की थी। लेकिन राजनीति के चलते यह विभाग ग्रामीण क्षेत्र तो दूर शहरों के लिये भी कोई स्थाई योजना नहीं बना पाया है। राजधानी नगर शिमला के लिये ऐसी स्थाई योजना की एकदम आवश्यकता थी लेकिन 1979 में जो अंतरिम योजना जारी हुई उसमें भी एनजीटी का फैसला आने तक 9 बार रिटैन्शन पॉलिसीयां जारी हुई और हर पॉलिसी में अवैधता का अनुमोदन किया। यहां तक की एन.जी.टी. का फैसला आने के बाद भी हजारों अवैध निर्माण खड़े हो गये। सरकार स्वयं फैसले के उल्लंघनकर्ताओं में शामिल है। शायद सरकार के किसी भी निर्माण का नक्शा कहीं से भी पारित नहीं है। जबकि टी.सी.पी. नियमों के अनुसार हर सरकारी भवन का नक्शा पास होना आवश्यक है।

राजधानी नगर शिमला के कई हिस्से स्लाइडिंग और सिंकिंग जोन घोषित हैं। इनमें कायदे से कोई निर्माण नहीं होना चाहिए था। लेकिन यहां निर्माण हुए हैं। पहाड़ में 35 डिग्री से ज्यादा के ढलान पर निर्माण नहीं होना चाहिए। लेकिन सरकारी निर्माण भी हुये हैं। जब सरकारी भवन ही कई – कई मंजिलों के बन गये तो प्राइवेट सैक्टर को कैसे रोका जा सकता था। ऐसे बहुमंजिला भवनों की एक लंबी सूची विधानसभा के पटल पर भी आ चुकी है लेकिन वह रिकार्ड का हिस्सा बनकर ही रह गई है। आज शिमला में जो तबाही हुई है उसका एक मात्र कारण निर्माण की अवैधताएं हैं जिन्हें रोक पाना शायद किसी भी सरकार के बस में नहीं रह गया है। सुक्खू सरकार ने भी इसी दबाव में आकर ऐटिक और बेसमैन्ट का फैसला लिया है। जब सरकार के अपने भवन ही असुरक्षित होने लग जायें तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि शिमला कितना सुरक्षित रह गया है। इस विनाश के बाद शिमला की सुरक्षा को लेकर हर मंच पर सवाल उठ रहे हैं। पिछले चार दशको में हुए शिमला के विकास ने आज जहां लाकर खड़ा कर दिया है उसके बाद यह सामान्य सवाल उठने लग गया है कि भविष्य को सामने रखते अब राजधानी को शिमला से किसी दूसरे स्थान पर ले जाने पर गंभीरता से विचार करने का समय आ गया है। एन.जी.टी. ने कुछ कार्यालय शिमला से बाहर ले जाने के निर्देश दिए हुए हैं। लेकिन अब कार्यालयों की जगह राजधानी को ही शिफ्ट करने पर विचार किया जाना चाहिए।

किसानों के जीवन में सफलता के स्वर्णिम बीज बो रहा कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर

कौशल संवर्धन से सशक्त बन रहे हिमाचल के किसान, फ्री ट्रेनिंग से खेती को दे रहे नए आयाम

हिमाचल के सुंदरनगर में स्थित कृषक प्रशिक्षण केंद्र प्रदेश के किसानों के जीवन में सफलता के स्वर्णिम बीज बो रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र में छोटी अवधि के विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम के जरिये प्रदेशभर के किसानों को नये समय में आधुनिक तरीके से खेती के लिए तैयार किया जाता है।

जिलाधीश मंडी अरिंदम चौधरी का कहना है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का हिमाचल के किसानों को कौशल संवर्धन से सशक्त बनाने पर विशेष ध्यान है। मुख्यमंत्री का फोकस है कि छोटे और सीमांत किसानों के लिए खेतीबाड़ी आर्थिक रूप से अधिक संभावनाओं से संपन्न बने। इस दृष्टि से कृषक प्रशिक्षण केंद्र को और सुदृढ़ करने तथा उभरते कृषि क्षेत्रों में विशेष प्रशिक्षण मॉडयूल डिजाइन करने का काम किया गया है।

डीसी का कहना है कि मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देशानुसार व्यावहारिक प्रशिक्षण से किसानों के उज्ज्वल भविष्य की मजबूत नींव रखने का काम कर रहा यह केंद्र अपने महत्वपूर्ण योगदान से किसानों का सच्चा साथी बन गया है। हिमाचल के किसान यहां आधुनिक तरीके से खेती के नए गुर सीखने और कौशल संवर्धन से सशक्त बनकर खेती को नए आयाम दे रहे हैं।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर की प्रधानाचार्य डॉ. प्राची बताती हैं कि वर्तमान में प्रशिक्षण केंद्र संपूर्ण हिमाचल के किसानों और कृषि विभाग की प्रशिक्षण जरूरतों को पूरा कर रहा है।

डॉ. प्राची बताती हैं कि वर्तमान में हिमाचल प्रदेश राज्य आजीविका मिशन द्वारा प्रायोजित मिलेटस के उत्पादन व विपणन पर कार्यक्रम चल रहा है। इसके अलावा यह केंद्र कृषि विस्तार डिप्लोमा फॉर इनपुट डीलर्स (डीएईएसआई) के आयोजन के लिए नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में भी कार्य कर रहा है।

डॉ. प्राची का कहना है कि प्रशिक्षण केंद्र का उद्देश्य सरकार की कृषि योजनाओं को किसानों तक पहुंचाना, खेती – किसानी के कार्य में दक्षता लाना, आधुनिकतम कृषि तकनीकों को किसानों तक पहुंचाना तथा समग्र रूप से व्यक्तियों और विभाग के बेहतर प्रदर्शन के लिए आवश्यक पेशेवर ज्ञान और कौशल को अद्यतन करना और बढ़ाना है। साथ ही प्रत्येक प्रशिक्षु में सही मनोवृत्ति अभिविन्यास लाना भी प्रशिक्षण केंद्र का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है।

कृषि विभाग मंडी के उपनिदेशक राजेश डोगरा बताते हैं कि यह केंद्र किसानों के साथ साथ कृषि विभाग के अधिकारियों – कर्मचारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को भी पूरा करता है।

साथ ही प्रशिक्षण केंद्र द्वारा कृषि विकास योजनाओं का कार्यान्वयन, किसानों को आधुनिक कृषि पद्धतियों के प्रदर्शन, किसानों की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न उद्यमियों के लिए प्रशिक्षण का आयोजन करके कृषि उत्पादन, जैविक नियंत्रण के माध्यम से कृषि फसल सुरक्षा के लिए एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम) को बढ़ावा देने का कार्य किया जाता है।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर, कृषि विभाग के जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं को बुनियादी प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए व्यावसायिक कृषि विद्यालय के रूप में वर्ष 1961 – 62 में अस्तित्व में आया था। बाद में किसानों को नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी के बारे में शिक्षित करने के उद्देश्य से वर्ष 1971 – 72 में इसे कृषक प्रशिक्षण केंद्र के रूप में चलाया गया।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र में एक सामुदायिक केंद्र और प्रशिक्षण हॉल है, जिसमें प्रशिक्षण के लिए आधुनिक ऑडियो विजुअल सुविधाएं भी उपलब्ध हैं। केंद्र में दो किसान छात्रावास हैं, जिनमें प्रशिक्षुओं को मुफ्त भोजन और आवास की सुविधा प्रदान की जाती है।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र में किसानों के प्रशिक्षण के साथ साथ प्रबंधकीय प्रशिक्षण में टीम का निर्माण, तनाव प्रबंधन, कृषि विस्तार प्रबंधन आदि प्रशिक्षण भी दिए जाते हैं। इसके अलावा लिपिक वर्ग के लिए कार्यालय प्रबंधन, रिकॉर्ड रखना, सेवा नियमावली का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। चतुर्थ श्रेणी के श्रमिकों जैसे चौकीदार व बेलदार के लिए भी प्रशिक्षण दिया जाता है। सरकार की योजनाओं के लिए कृषि विभाग के आतमा, डीआरडीए या जायका द्वारा प्रायोजित आवश्यकता आधारित कार्यक्रमों के प्रशिक्षण दिए जाते हैं।

वहीं, तकनीकी वर्ग के कृषि प्रसार अधिकारियों को आधुनिकतम तकनीकों की जानकारी दी जाती है। सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए मिलेट्स का उत्पादन एवं उसका विपणन, जलवायु लचीली कृषि, प्राकृतिक खेती इत्यादि के क्षेत्र में भी प्रशिक्षण दिया जाता है।

कृषक प्रशिक्षण केंद्र सुंदरनगर से ट्रेनिंग लेकर हजारों की संख्या में प्रदेश के किसान खेती से जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने में कामयाब रहे हैं। वे सभी एक स्वर में हिमाचल सरकार का धन्यवाद करते हुए कहते हैं कि सुंदरनगर कृषक प्रशिक्षण केंद्र अपनी खेती के तरीकों को बढ़ाने के लिए मार्गदर्शन चाहने वाले किसानों के लिए आशा की किरण बन गया है।

ऐसे हजारों लाभार्थियों में से एक बिलासपुर जिले की लाभार्थी प्रशिक्षु सुनीता गौतम बताती हैं कि उन्होंने यहां मोटे अनाज की ट्रेनिंग लेकर बड़े पैमाने पर काम आरंभ किया है। प्रशिक्षण में उन्हें हरेक सैद्धांतिक पहलू को प्रैक्टिकल रूप से भी बताया गया, जो उन्हें बहुत काम आया। एक अन्य लाभार्थी प्रशिक्षु अनीता कहती हैं कि यहां किसानों को आधुनिक कृषि की राह पर चलने में सहायता मिल रही है और उनके विकास में भागीदारी सुनिश्चित हो रही है।

77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के संबोधन की मुख्य बातें

मेरे प्रिय 140 करोड़ परिवारजन, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र और अब बहुत लोगों का अभिप्राय है ये जनसंख्या की दृष्टि से भी हम विश्व में नंबर एक पर हैं। मैं देश के कोटि – कोटि जनों को, देश और दुनिया में भारत को प्यार करने वाले, भारत का सम्मान करने वाले, भारत का गौरव करने वाले कोटि – कोटि जनों को आजादी के इस महान पवित्र पर्व की अनेक – अनेक शुभकामनाएं देता हूं।

आज 15 अगस्त महान क्रांतिकारी और अध्यात्म जीवन के रूचि तुल्य प्रणेता श्री अरविंदों की 150वीं जयंती पूर्ण हो रही है। ये वर्ष स्वामी दयानंद सरस्वती के 150वीं जयंती का वर्ष है। ये वर्ष रानी दुर्गावती के 500वीं जन्मशती का बहुत ही पवित्र अवसर है जो पूरा देश बड़े धूमधाम से मनाने वाला है। ये वर्ष मीराबाई भक्ति योग की सिरमौर मीराबाई के 525 वर्ष का भी ये पावन पर्व है। इस बार जो 26 जनवरी हम मनाएंगे वो हमारे गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ होगी।

पिछले कुछ सप्ताह नार्थ – ईस्ट में विशेषकर मणिपुर में और हिन्दुस्तान के अन्य कुछ भागो में, लेकिन विशेषकर मणिपुर में जो हिंसा का दौर चला, कई लोगों को अपना जीवन खोना पड़ा, मां – बेटियों के सम्मान के साथ खिलवाड़ हुआ, लेकिन कुछ दिनों से लगातार शांति की खबरें आ रही हैं, देश मणिपुर के लोगों के साथ है।

यह हमारा सौभाग्य है कि भारत के इस अमृतकाल में, जो हम करेंगे, जो कदम उठाएंगे, जितना त्याग करेंगे, तपस्या करेंगे, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, एक के बाद एक फैसले लेंगे, आने वाले एक हजार साल का देश का स्वर्णिम इतिहास उससे अंकुरित होने वाला है।

भारत माँ 140 करोड़ देशवासियों के पुरुषार्थ से, उनकी चेतना से, उनकी ऊर्जा से फिर एक बार जागृत हो चुकी है। मैं साफ देख रहा हूँ दोस्तों, यही कालखंड है, पिछले 9 – 10 साल हमने अनुभव किया है। आज हमारे पास डेमोग्राफी है, आज हमारे पास डेमोक्रेसी है, आज हमारे पास डाइवर्सिटी है। डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी की ये त्रिवेणी भारत के हर सपने को साकार करने का सामर्थय रखती है।

मेरे युवाओं ने भारत को दुनिया पहले तीन स्टार्टअप इकोनॉमी सिस्टम में स्थान दिला दिया है। विश्व के युवाओं को अचम्भा हो रहा है। भारत के इस सामर्थय को लेकर के, भारत की इस ताकत को देखकर के। आज दुनिया टेक्नोलॉजी ड्रिवेन है और आने वाला युग टेक्नोलॉजी से प्रभावित रहने वाला है और तब टेक्नोलॉजी में भारत की जो टेलेंट है, उसकी एक नई भूमिका रहने वाली है।

भारत जो कमाल कर रहा है, मेरे टियर – 2, टियर – 3 सिटी के युवा भी आज मेरे देश का भाग्य गढ़ रहे हैं। हमारे छोटे – छोटे शहर, हमारे कस्बे आकार और आबादी में छोटे हो सकते हैं, लेकिन आशा और आकांक्षा, प्रयास और प्रभाव वो किसी से कम नहीं है, वो सामर्थय उनके अंदर है।

राष्ट्रीय चेतना वो एक ऐसा शब्द है जो हमें चिंताओं से मुक्त कर रहा है। राष्ट्रीय चेतना यह सिद्ध कर रही है कि भारत का सबसे बड़ा सामर्थय बना है, जन – जन का सरकार पर विश्वास, जन – जन का देश के उज्जवल भविष्य पर विश्वास और विश्व का भी भारत के प्रति विश्वास।

आज देश में जी – 20 समिट की मेहमान नवाजी का भारत को अवसर मिला है। और पिछले एक साल से हिन्दुस्तान के हर कोने में जिस प्रकार से जी – 20 के अनेक ऐसे आयोजन हुए हैं, अनेक कार्यक्रम हुए हैं, उसने देश के सामान्य मानव के सामर्थय को विश्व को परिचित करा दिया है।

मैं साफ – साफ देख रहा हूं कि कोरोना के बाद एक नया विश्व ऑर्डर, एक नया ग्लोबल ऑर्डर, एक नया जियो पॉलिटिकल इक्वेशन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जियो पॉलिटिकल इक्वेशन की सारी व्याख्याएं बदल रही है, परिभाषाएं बदल रही है।

आज भारत ग्लोबल साउथ की आवाज बन रहा है। भारत की समृद्धि, विरासत आज दुनिया के लिए एक अवसर बन रही है।

देश के पास आज ऐसी सरकार है, वो सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय देश के संतुलित विकास के लिए समय का पल – पल और जनता की पाई – पाई जनता की भलाई के लिए लगा रही है और मेरी सरकार, मेरे देशवासियों का मान एक बात से जुड़ा हुआ है, हमारे हर निर्णय, हमारी हर दिशा, उसका एक ही मानदंड है Nation First राष्ट्र प्रथम और राष्ट्र प्रथम यही दूरगामी परिणाम, सकारात्मक परिणाम पैदा करने वाला है।

ब्यूरोक्रेसी ने transform करने के लिए perform की जिम्मेदारी बखूबी निभाई और जनता – जनार्दन उनसे जुड़ गई तो वो transform होता भी नजर आया। reform, perform, transform ये कालखंड अब भारत के भविष्य को गढ़ रहा है। और हमारी सोच देश की उन ताकतों को बढ़ावा देने पर है, जो आने वाले एक हजार साल की नींव को मजबूत करने वाले हैं।

हमने जल शक्ति मंत्रालय बनाया ये जल शक्ति मंत्रालय हमारा, हमारे देश के एक – एक देशवासियों को पीने का शुद्ध पानी पहुंचे।

हमारे देश में कोरोना के बाद दुनिया देख रही है holistic health care ये समय की मांग है। हमने अलग आयुष मंत्रालय बनाया और योग और आयुष आज दुनिया में अपना परचम लहरा रहे हैं।

मत्स्य पालन हमारा इतना बड़ा समुद्री तट, हमारे कोटि – कोटि मछुआरे भाई – बहन उनका कल्याण भी हमारे दिलों में है और इसलिए हमने अलग से मत्स्य पालन को लेकर के, पशुपालन को लेकर के, डेरी को लेकर के अलग मंत्रालय की रचना की ताकि समाज के जिस वर्ग के लोग पीछे रह गए उनको हम साथ दे।

आज मैं देशवासियों को बताना चाहता हूं कि जब देश आर्थिक रूप से समृद्ध होता है तो सिर्फ तिजोरी नहीं भरती है, देश का सामर्थ्य बढ़ता है, देशवासियों का सामर्थ्य बढ़ता है और तिजोरी का पाई – पाई अगर ईमानदारी से जनता – जनार्दन के लिए खर्च करने का संकल्प लेने वाली सरकार हो तो परिणाम कैसा आता है। मैं 10 साल का हिसाब तिरंगे की साक्षी में लाल किले की प्राचीन से मेरे देशवासियों को दे रहा हूं।

10 साल पहले राज्यों को 30 लाख करोड़ रूपये भारत सरकार की तरफ से जाते थे। पिछले 9 साल में ये आंकड़ा 100 लाख करोड़ पर पहुंचा है। पहले स्थानीय निकाय के विकास के लिए भारत सरकार के खजाने से 70 हजार करोड़ रूपया जाता था, आज वो 3 लाख करोड़ से भी ज्यादा जा रहा है। पहले गरीबों के घर बनाने के लिए 90 हजार करोड़ रूपया खर्च होता था आज वो 4 गुना होकर के 4 लाख करोड़ से भी ज्यादा खर्च गरीबों के घर बनाने के लिए हो रहा है।

सरकार 10 लाख करोड़ रुपया किसानों को यूरिया में सब्सिडी दे रही है। मुद्रा योजना के तहत 20 लाख करोड़ रुपए और उससे भी ज्यादा देश के नौजवानों को स्वरोजगार के लिए दिए हैं। 8 करोड़ लोगों ने नया कारोबार शुरू किया है।

इन सारे प्रयासों का परिणाम है कि आज 5 साल के मेरे एक कार्यकाल में, 5 साल में साढ़े 13 करोड़ मेरे गरीब भाई – बहन गरीबी की जंजीरों को तोड़ करके न्यू मिडिल क्लास के रूप में बाहर आए हैं। जीवन में इससे बड़ा कोई संतोष नहीं हो सकता।

हमारे सुनार हों, हमारे राजमिस्त्री हों, हमारे कपड़े धोने का काम करने वाले लोग हों, हमारे बाल काटने वाले भाई – बहन परिवार हों, ऐसे लोगों को एक नई ताकत देने के लिए हम आने वाले महीने में विश्वकर्मा जयन्ती पर विश्वकर्मा योजना लॉन्च करेंगे और करीब 13 – 15 हजार करोड़ रुपये से उसका प्रारंभ करेंगे।

हमने पीएम किसान सम्मान निधि में ढाई लाख करोड़ रुपया सीधा किसानों के खाते में जमा किया है। जल जीवन मिशन के तहत दो लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। हमने आयुष्मान भारत योजना के तहत 70 हजार करोड़ रुपये लगाए हैं। हमने पशुधन को बचाने के लिए करीब – करीब 15 हजार करोड़ रुपया पशुधन के टीकाकरण के लिए लगाया है।

हमने जन – औषधि केंद्र से जो दवाई बाजार में सौ रुपये में मिलती है वो 10 रुपया, 15 रुपया, 20 में दी। अब देश में 10 हजार जन – औषधि केंद्र से हम 25 हजार जन – औषधि केंद्र का लक्ष्य लेकर के आने वाले दिनों में काम करने वाले हैं।

मध्यम वर्गीय परिवार जो अपने खुद के घर का सपना देख रहे हैं। हम उसके लिए भी आने वाले कुछ सालों के लिए एक योजना लेकर के आ रहे हैं। सरकार ने उन्हें बैंक से लोन पर ब्याज के अंदर राहत देकर लाखों रुपयों की मदद करने का निर्णय किया है।

भारत ने महंगाई को नियंत्रित रखने के लिए भरसक प्रयास किए हैं। पिछले कालखंड की तुलना में हमें कुछ सफलता भी मिली है लेकिन इतने से संतोष नहीं मान सकते। दुनिया से हमारी चीजें अच्छी हैं, इतनी बात से हम सोच नहीं सकते, देशवासियों का महंगाई का बोझ कम से कम हो, इस दिशा में और भी कदम उठाने हैं।

आज देश Renewable energy में काम कर रहा है, आज देश green hydrogen पर काम हो रहा है, देश की space में क्षमता बढ़ रही है।

देश deep sea mission में भी सफलता के साथ आगे चल रहा है। देश में रेल आधुनिक हो रही है, तो वंदे भारत, बुलेट ट्रेन भी आज देश के अंदर काम कर रही है। गांव – गांव पक्की सड़कें बन रही है तो इलेक्ट्रिक बसें, मेट्रो की रचना भी आज देश में हो रहे हैं। आज गांव – गांव तक इंटरनेट पहुंच रहा है तो quantum computer के लिए भी देश तय करता है। Nano Urea और Nano DAP उस पर काम हो रहा है तो दूसरी तरफ जैविक खेती पर भी हम बल दे रहे हैं।

इन दिनों जो मैं शिलान्यास कर रहा हूं न आप लिख करके रखिए उसके उद्घाटन भी आप सबने मेरे नसीब में ही छोड़े हुए हैं। हमारी कार्य संस्कृति, बड़ा सोचना, दूर का सोचना, सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सोचना यह हमारी कार्यशैली रही है।

आज करीब – करीब 75 हजार अमृत सरोवर का काम निर्माण हो रहा है। यह अपने आप में बहुत बड़ा काम हो रहा है। जनशक्ति और जलशक्ति की यह ताकत भारत के पर्यावरण की रक्षा में भी काम आने वाली है। 18 हजार गांवों तक बिजली पहुंचाना, जन तक बैंक खाते खोलना, बेटियों के लिए शौचालय बनाना सारे टारगेट समय के पहले पूरी शक्ति से पूरे करेगा।

दुनिया में सबसे तेज गति से 5 – G रोल आउट करने वाला मेरा देश है। 700 से अधिक जिलों तक हम पहुंच चुके हैं। और अब 6 – G की भी तैयारी कर रहे हैं। हमने टास्क फोर्स बना दिया है। renewable energy हम टारगेट से पहले चले हैं। हमने renewable energy 2030 का जो टारगेट तय किया था, 21 – 22 में उसका पूरा कर दिया।

हमने समय से पहले नई संसद बना दी। यह काम करने वाली सरकार है, निर्धारित लक्ष्यों को पार करने वाली सरकार है, यह नया भारत है, यह आत्मविश्वास से भरा हुआ भारत है, यह संकल्पों को चरितार्थ करने के लिए जी – जान से जुटा हुआ भारत है।

आंतरिक सुरक्षा की स्थिति : आज देश में आतंकी हमलों में भारी कमी आयी है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में भी बहुत बड़ा बदलाव आया है, बहुत बड़ा परिवर्तन का एक वातावरण बना है। देश की आंतरिक सुरक्षा संभालने वाले यूनिफॉर्म फोर्सेस, मैं आजादी के इस पावन पर्व पर उनको भी अनेक – अनेक बधाई देता हूं।

दुनिया में जिन – जिन देशों ने प्रगति की है, दुनिया में जो – जो देश संकटों को पार करके निकले हैं, उनमें हर चीज के साथ – साथ एक महत्वपूर्ण कैटेलिक एजेंट रहा है, वो राष्ट्रीय चरित्र रहा है। और हमें राष्ट्रीय चरित्र के लिए और बल देते हुए हमें आगे बढ़ना होगा।

women-led development : देश में आगे बढ़ने के लिए एक अतिरिक्त शक्ति का सामर्थ्य भारत को आगे ले जाने वाला है और वो है women-led development, आज भारत गर्व से कह सकता है कि दुनिया में नागरिक उड्डयन में अगर किसी एक देश में सबसे ज्यादा women-pilot हैं तो मेरे देश में हैं। आज चन्द्रयान की गति हो, moon-mission की बात हो, मेरी women-scientist उसका नेतृत्व कर रही हैं।

आज 10 करोड़ महिलाएं women self help में जुड़ी हुई हैं और women self help group के साथ आप गांव में जाएंगे तो आपको बैंक वाली दीदी मिलेगी, आपको आंगनबाड़ी वाली दीदी मिलेगी, आपको दवाई देने वाली दीदी मिलेगी और अब मेरा सपना है, गांवों में 2 करोड़ लखपति दीदी बनाने का।

भारत विविधताओं से भरा देश है। असंतुलित विकास के हम शिकार रहे हैं, मेरा – पराया के कारण हमारे देश के कुछ हिस्से उसके शिकार रहे हैं। अब हमें regional aspirations को पूरा करने के लिए संतुलित विकास को बल देना है।

भारत एक mother of democracy है, भारत model of diversity भी है। भाषाएं अनेक हैं, बोलियां अनेक हैं, परिधान अनेक हैं, विविधताएं बहुत है। हमने उन सारो के आधार पर आगे बढ़ना है। आज जब अफगानिस्तान से गुरूग्रंथ साहब के स्वरूप को लाते है तो पूरा देश गौरव की अनुभूति करता है।

आज देश आधुनिकता की तरफ बढ़ रहा है। Highway हो, Railway हो, Airway हो, I-Ways हो, Information Ways,Water Ways हो, कोई क्षेत्र ऐसा नहीं है, जिस क्षेत्र को आगे बढ़ाने की दिशा में आज देश काम न करता हो। पिछले 9 वर्ष में तटीय क्षेत्रों में, हमने आदिवासी क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में विकास को बहुत बल दिया है।

हमने मातृभाषा में पढ़ाने पर बदल दिया है और मातृभाषा की दिशा में, मैं भारत के सुप्रीम कोर्ट का भी धन्यवाद करता हूँ, जिसने कहा है कि वे अब जो judgement देंगे, उसका जो operative part होगा, वो जो अदालत में आया है, उसकी भाषा में उसको उपलब्ध्य होगा।

हमने वहां Vibrant Border Village का एक कार्यक्रम शुरू किया है और Vibrant Border Village अब तक इसके लिए कहा जाता था देश के आखिरी गांव, हमने उस पूरी सोच को बदला है। वो देश का आखिरी गांव नहीं है, सीमा पर जो नजर आ रहा है, वो मेरे देश का पहला गांव है।

हमने संतुलित विकास के लिए Aspirational District, Aspirational Block की कल्पना की और आज उसके सुखद परिणाम मिल रहे हैं। आज राज्य के जो Normal Parameters हैं, जो Aspirational Districts कभी बहुत पीछे थे, वो आज राज्य में भी अच्छा करने लग गए हैं।

हम विश्व मंगल की बात को कैसे आगे बढ़ाते हैं। हमने कहा one sun, one world, one grid renewable energy के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा हमारा statement है, आज दुनिया उसको स्वीकार कर रही है।

हमने क्लाईमेट को लेकर के दुनिया को रास्ता दिखाया है, लाइफ मिशन लॉन्च किया है life style for environment हमने दुनिया के सामने मिलकर international solar alliance बनाया और आज दुनिया के कई देश international solar alliance का हिस्सा बन रहे हैं।

सपने अनेक हैं, संकल्प साफ है, नीतियाँ स्पष्ट हैं। नियत के सामने कोई सवालिया निशान नहीं है। लेकिन कुछ सच्चाईयों को हमें स्वीकार करना पड़ेगा और उसके समाधान के लिए मेरे प्रिय परिवारजनों, मैं आज लालकिले से आपकी मदद मांगने आया हूं, मैं लालकिले से आपका आर्शीवाद मांगने आया हूं।

आजादी के अमृतकाल में 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएंगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा – झंडा विकसित भारत का तिरंगा – झंडा होना चाहिए, रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे हटना नहीं है।

हमारे देश की सारी समस्याओं की जड़ में भ्रष्टाचार है जिसने दीमक की तरह देश की सारी व्यवस्थाओं को, देश के सारे सामर्थ्य को पूरी तरह नोंच लिया है। मेरे प्रिय परिवारजनों, यह मोदी के जीवन का कमेंटमेंट है, यह मेरे व्यक्तित्व का एक कमेंटमेंट है कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता रहूंगा।

दूसरा हमारे देश को नोंच लिया है परिवारवाद ने। इस परिवारवाद ने देश को जिस प्रकार से जकड़ करके रखा है उसने देश के लोगों का हक छीना है, और तीसरी बुराई तुष्टिकरण की है। यह तुष्टिकरण में भी देश के मूल चिंतन को, देश के सर्वसमावेशक हमारे राष्ट्रीय चरित्र को दाग लगा दिए हैं।

मैं जब 2014 में आपके पास आया था तब 2014 में मैं परिवर्तन का वादा लेकर के आया था। 2014 में मैंने आपको वादा किया था मैं परिवर्तन लाऊंगा। और 140 करोड़ मेरे परिवारजन आपने मुझ पर भरोसा किया और मैंने विश्वास पूरा करने की कोशिश की। Reform, Perform, Transform वो 5 साल जो वादा था वो विश्वास में बदल गया।

मुझे विश्वास है हमारे पूर्वजों ने आजादी के लिए जो जंग लड़ा था, जो सपने देखे थे, वो सपने हमारे साथ हैं। आजादी के जंग में जिन्होंने बलिदान दिया था, उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं और 140 करोड़ देशवासियों के लिए एक ऐसा अवसर आया है, ये अवसर हमारे लिए एक बहुत बड़ा संबल लेकर के आया है।

आज जब मैं अमृतकाल में आपके साथ बात कर रहा हूं, ये अमृतकाल का पहला वर्ष है, ये अमृतकाल के पहले वर्ष पर जब मैं आपके बात कर रहा हूं तो मैं आपको पूरे विश्वास से कहना चाहता हूं – चलता चलाता कालचक्र, अमृतकाल का भालचक्र, सबके सपने, अपने सपने, पनपे सपने सारे, धीर चले, वीर चले, चले युवा हमारे, नीति सही रीती नई, गति सही राह नई, चुनो चुनौती सीना तान, जग में बढ़ाओ देश का नाम।

ये अमृतकाल हम सबको मां भारती के लिए कुछ कर गुजरने का काल है। आजादी का जब जंग चल रहा था, 1947 के पहले जो पीढ़ी ने जन्म लिया था, उन्हें देश के लिए मरने का मौका मिला था। वो देश के लिए मरने के लिए मौका नहीं छोड़ते थे, लेकिन हमारे लिए देश के लिए जीने का इससे बड़ा कोई अवसर नहीं हो सकता।

140 करोड़ देशवासियों के संकल्प को सिद्धि में भी परिवर्तित करना है और 2047 का जब तिरंगा झंडा फहरेगा, तब विश्व एक विकसित भारत का गुणगान करता होगा। इसी विश्वास के साथ, इसी संकल्प के साथ मैं आप सबको अनेक – अनेक शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत – बहुत बधाई देता हूँ।

विषम भौगोलिक स्थिति के दृष्टिगत प्रदेश को दिया जाए विशेष राहत पैकेज:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रदेश में आपदा से हुए भारी नुकसान के संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा और केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर के साथ विस्तृत चर्चा की।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने आपदा से प्रदेश में हुए भारी नुकसान की विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने राज्य में स्थितियां सामान्य करने के प्रदेश सरकार के प्रयासों को बल देने के लिए केदारनाथ और भुज त्रासदियों की तर्ज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने की अपील की। आपदा के कारण हुए भारी नुकसान को रेखांकित करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति को व्यापक नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की वर्तमान राहत नियमावली के अनुरूप वित्तीय प्रावधान हिमाचल प्रदेश में हुए नुकसान की पूर्ति के लिए अपर्याप्त है। उन्होंने राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और आपदा की गंभीरता को देखते हुए विशेष राहत पैकेज का आग्रह किया।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने

केंद्र सरकार द्वारा अंतरिम राहत की पहली किस्त देरी से जारी करने का मामला भी उठाया। उन्होंने जगत प्रकाश नड्डा और अनुराग सिंह ठाकुर से वित्तीय सहायता प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि मानसून के दौरान भारी बारिश और भूस्खलन के कारण आई प्राकृतिक आपदा से प्रदेश को 10 हजार करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा आकलन टीमें भेजे जाने के बावजूद अंतरिम राहत अभी भी लंबित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार प्रभावितों को सहायता प्रदान करने के लिए अपने सीमित संसाधनों का उपयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के तहत वार्षिक दो किश्तों में दिए जाने वाले 360 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि ऑडिट आपत्तियों को दूर करने के राज्य सरकार के प्रयासों के फलस्वरूप केंद्र सरकार ने लम्बित 315 करोड़ रुपये में से 189 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। उन्होंने शेष 126 करोड़ रुपये शीघ्र प्रदान करने की आग्रह किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 अगस्त, 2023 तक प्रदेश सरकार ने केन्द्र सरकार को राज्य में हुए नुकसान की विस्तृत रिपोर्ट भेजकर 6,700 करोड़ रुपये क्लेम किए हैं।

ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने संरचनात्मक इंजीनियरिंग और जल निकासी प्रणालियों के सुधार और सुढ़ीकरण के राज्य सरकार के प्रयासों की भी विस्तृत जानकारी दी। उन्होंने शिमला के पास जाठिया देवी में एक नए शहर को स्थापित करने की योजना के बारे में भी बताया।

भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने प्राकृतिक आपदा के कारण प्रदेश को हुए नुकसान की भरपाई के दृष्टिगत राज्य को पर्याप्त सहायता देने के लिए केंद्र सरकार की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने आश्वासन दिया कि अंतरिम राहत की पहली किस्त शीघ्र जारी करने की दिशा में प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने संकट के इस समय में राज्य को पूर्ण सहयोग प्रदान करने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संकल्प को दोहराया। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त धनराशि सुनिश्चित करने के लिए संकल्पबद्ध है।

बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर और नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने भी अपने विचार व्यक्त किए।

इस अवसर पर सांसद सुरेश कश्यप और सिकंदर कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डॉ.राजीव बिंदल, पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज, विधायक बलबीर वर्मा, पूर्व विधायक राम लाल मारकंडा, मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव भरत खेड़ा, मुख्यमंत्री के प्रधान निजी सचिव विवेक भाटिया अन्य गणमान्य व्यक्ति और वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

किन्नौर के लिए वैकल्पिक मार्गों पर कार्य करे सीमा सड़क संगठन:विक्रमादित्य सिंह

शिमला/शैल। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह की अध्यक्षता में प्रदेश में भारी बारिश के कारण क्षतिग्रस्त सड़कों की बहाली के लिए लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी कार्यों की समीक्षा के लिए एक वर्चुअल बैठक आयोजित की गई। इसमें विभाग के सभी जोन

के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि पूरे प्रदेश में भारी बरसात से सड़कों को बड़े स्तर पर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि अभी तक प्रदेश में 600 से अधिक सड़क मार्ग बाधित हैं और इन्हें खोलने के लिए दैनिक आधार पर तय लक्ष्यों के अनुरूप कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आगामी तीन दिनों में लगभग 550 सड़कों की बहाली का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि तय समय अवधि में यह सड़कें बहाल करने के लिए युद्ध स्तर पर कार्य करें।

लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वे साप्ताहिक आधार पर सभी चार जोन की बारी-बारी से वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि हाल ही में हुई भारी बारिश से सड़कों को बड़े स्तर पर हुए नुकसान का एक कारण समुचित ड्रेनेज सुविधा का अभाव भी रहा है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश में सभी सड़कों पर ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज सहित बाधित कलवर्ट खोलने को प्राथमिकता प्रदान की जाये। उन्होंने कहा कि इस बारे में मुख्यमंत्री के निर्देशों के अनुरूप विभाग पूरी गंभीरता से कार्य सुनिश्चित करेगा।

उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से अतिरिक्त मशीनरी की खरीद के लिए 30 करोड़ रुपये विभाग को उपलब्ध करवाए गए हैं और इसकी खरीद की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण की जाए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार भी व्यक्त किया। उन्होंने आवश्यकता के अनुसार किराए पर भी मशीनरी लगाने के निर्देश दिए।

बैठक में बताया गया कि मंडी जिला में मंडी-कमांद-कटौला सड़क, पंडोह-चौलचौक-सुन्दरनगर सड़क पर यातायात सुचारू कर दिया गया है। कुल्लू जिला के लिए पंडोह से कैंचीमोड़ तक बीबीएमबी के सहयोग से सड़क निर्मित करने का कार्य जारी है और यहां से शीघ्र ही यातायात बहाल कर दिया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि कुल्लू घाटी को जोड़ने वाले इस महत्वपूर्ण सड़क मार्ग की निरन्तर निगरानी सुनिश्चित की जाए और यहां पर्याप्त मशीनरी एवं स्टाफ की तैनाती रखी जाए। कुल्लू से मनाली की तरफ वामतट सड़क मार्ग सभी वाहनों के लिए खोल दिया गया है।

लोक निर्माण मंत्री ने कांगड़ा जिला के जयसिंहपुर, भवारना तथा नगरोटा मंडल में क्षतिग्रस्त सड़कों की शीघ्र बहाली के भी निर्देश दिए। उन्होंने सोलन जिला के चक्की मोड़ में बार-बार मलबा गिरने के दृष्टिगत वैकल्पिक सम्पर्क मार्गों की बहाली एवं रख-रखाव पर विशेष ध्यान केन्द्रित करने को भी कहा। शिमला जिला के सेब बहुल क्षेत्रों में अधिकांश सड़कें 22 अगस्त तक बहाल करने के निर्देश भी दिए।

इससे पूर्व लोक निर्माण मंत्री ने सीमा सड़क संगठन के अधिकारियों के साथ भी एक बैठक की, जिसमें संगठन के तहत आने वाली सड़कों के उचित रख-रखाव पर चर्चा की गई। बैठक में बताया गया कि बीआरओ के तहत किन्नौर तक सड़क यातायात सुचारू है। इसके अतिरिक्त मनाली-सरचू सड़क मार्ग के लिए केन्द्र से 48 करोड़ रुपये उपलब्ध करवाने का आग्रह किया गया है। लोक निर्माण मंत्री ने सीमा सड़क संगठन से आग्रह किया कि किन्नौर के लिए पुराने हिन्दुस्तान-तिब्बत मार्ग सहित चार वैकल्पिक मार्गों पर भी कार्य करें ताकि सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण इस जिला से वर्षभर सड़क सम्पर्क कायम रखा जा सके।

बैठक में प्रधान सचिव लोक निर्माण विभाग भरत खेड़ा, लोक निर्माण विभाग के प्रमुख अभियन्ता अजय गुप्ता, सीमा सड़क संगठन के कर्नल विशाल गुलेरिया सहित अन्य वरिष्ठ विभागीय अधिकारी उपस्थित थे।

बैठक के उपरान्त पत्रकार वार्ता में लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि वर्तमान में हिमाचल एक बड़ी आपदा के दौर से गुजर रहा है और इसमें लोक निर्माण विभाग को अभी तक लगभग 2,600 करोड़ रुपये का नुकसान आंका गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रयासों से लोक निर्माण विभाग को सड़कों की बहाली के लिए मंडल स्तर तक पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-3 के अंतर्गत प्रदेश द्वारा भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त लगभग 2,683 किलोमीटर लम्बी ग्रामीण सड़कों के सुदृढ़ीकरण पर विशेष ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इसके लिए बरसात के बाद युद्ध स्तर पर कार्य आरम्भ किया जाएगा तथा विभाग का प्रयास रहेगा कि यह कार्य ग्लोबल टेंडर के माध्यम से सम्पन्न किए जाएं। इससे कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित होने के साथ ही अत्याधुनिक तकनीक का भी समावेश किया जा सकेगा।

जल निकासी प्रणाली की मजबूती के लिए व्यापक योजना विकसित की जाएगी:मुख्यमंत्री

शिमला/शैल। प्रदेश में शहरी जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और पहाड़ी अस्थिरता को रोकने के लिए उचित जल प्रबंधन की आवश्यकता है। राज्य सरकार जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने और निर्माण के लिए ठोस संरचनात्मक डिजाइन सिद्धांतों को एकीकृत करने के लिए एक व्यापक योजना विकसित की जाएगी। यह बात मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भूस्खलन प्रभावित शिमला के लालपानी क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात कही। उन्होंने आपदा प्रभावित क्षेत्र में नुकसान का जायजा लिया और जिला प्रशासन को राहत एवं बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिये।

मीडिया से अनौपचारिक बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन की समय पर प्रतिक्रिया से नुकसान काफी कम हो गया है क्योंकि इन घरों में रहने वाले लोगों को आसन्न खतरे के कारण पहले ही खाली करा लिया गया था।

उन्होंने कहा कि इन उपायों के अलावा राज्य सरकार एक व्यापक, दीर्घकालिक आपदा योजना तैयार कर रही है। इसके कार्यान्वयन के लिए लगभग 800 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा, जिसका उद्देश्य भविष्य की आपदाओं के प्रभाव को कम करना है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश के कारण 60 से अधिक लोगों की जान चली गई और यह संख्या बढ़ने की संभावना है। इसका प्रभाव शिमला में सबसे गंभीर रहा, जबकि कांगड़ा जिला के फतेहपुर में किसानों को फसल का नुकसान हुआ। पौंग बांध से पानी छोड़े जाने के कारण लगभग 300 लोगों के फंस जाने के बाद बचाव अभियान चलाया गया और सभी व्यक्तियों को सफलतापूर्वक बचा लिया गया। उन्होंने कहा कि लगातार भारी बारिश के कारण मंडी जिले में भी काफी नुकसान हुआ है।

मुख्यमंत्री ने आपदा के समय में नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर द्वारा केवल राजनीति करने पर निराशा व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार राहत और बचाव कार्यों पर दृढ़ता से ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने विपक्ष द्वारा इस संकट की स्थिति में विधानसभा के विशेष सत्र की मांग की उपयुक्तता पर सवाल उठाया। उन्होंने आश्वासन दिया कि राज्य सरकार दस दिवसीय विधानसभा सत्र आयोजित करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पुलिस कर्मियों की आपदा प्रतिक्रिया प्रयासों के लिए उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए उन्होंने अपने सुरक्षा कवर को भी कम किया है। उन्होंने विपक्ष से राजनीतिक दिखावे में उलझने के बजाये मौजूदा स्थिति की गम्भीरता को समझते हुए प्रदेश हित को प्राथमिकता देने को कहा।

युनम चोटी फतह करने पर मुख्यमंत्री ने महिला पुलिस आरक्षी को दी बधाई

शिमला/शैल। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल पुलिस की चौथी आईआरबी जंगलबेरी की पुलिस आरक्षी बिंदिया को हाल ही में लाहौल स्थित 6,111 मीटर ऊंची युनम चोटी की सफलतापूर्वक चढ़ाई करने पर बधाई दी है। बिंदिया ने अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण एवं संबद्ध खेल संस्थान, मनाली से मूलभूत एवं उच्च प्रशिक्षण प्राप्त किया है। मुख्यमंत्री ने बिंदिया को आगामी अभियानों के लिए शुभकामनाएं देते हुए कहा कि युनम चोटी पर विजय प्राप्त करने वाली वह राज्य पुलिस की पहली महिला हैं और यह पुलिस विभाग एवं समस्त प्रदेशवासियों के लिए गर्व का विषय है।

बिंदिया हमीरपुर जिले के नादौन क्षेत्र के कांगू गांव की रहने वाली हैं।

77वाँ स्वतंत्रता दिवस
15 अगस्त 2023

आज़ादी के 77वें साल की शुरुआत वीरों को नमन के साथ

स्वतंत्रता दिवस देश के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान देने वाले महानायकों को स्मरण करने का पावन अवसर है। आईये, देश की खातिर सर्वस्व न्योछावर करने वाले वीर शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करें और प्रदेश की उन्नति व खुशहाली के लिए एकजुट प्रयास करें।

स्वतंत्रता दिवस पर
समस्त प्रदेशवासियों को
हार्दिक शुभकामनाएं

सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

www.himachalpr.gov.in HimachalPradeshGovtIPRDept IPRHIMACHAL dprhp dprhimachal

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक श्री बलदेव शर्मा द्वारा ऋचा प्रिंटर्ज एण्ड पब्लिशर्ज़ रिवोली बस अड्डा लक्कड़ बाजार शिमला से प्रकाशित व मुद्रित दूरभाष: 0177 – 2805015, 94180 – 15015 फैक्स: 2805015

आपदा काल में सुरक्षित सरकारी भवन से कार्यालयों को निजी भवनों में ले जाना कितना सही

यू एस क्लब से सरकारी कार्यालयों की शिफ्टिंग क्यों?

शिमला/शैल। प्रदेश में राज्य आपदा घोषित है क्योंकि जान माल का अकल्पनीय नुकसान हुआ है। इसकी भरपाई करने में लम्बा समय लगेगा। सरकार वित्तीय संकट से जूझ रही है। मुख्यमंत्री ने सत्ता संभालते ही प्रदेश के हालात श्रीलंका जैसे होने की चेतावनी दी है। स्वभाविक है कि ऐसी चेतावनी सचिवालय में बैठी वरिष्ठ अफसरशाही द्वारा दिये गये फीडबैक पर आधारित रही होगी। इस वित्तीय चेतावनी के परिदृश्य में ही नये संसाधन जुटाने के उपाय सोचे गये होंगे। जल-उपकर के लिये अध्यादेश तक लाया गया। डीजल पर दो बार वैट बढ़ाया गया। बिजली पानी और कूड़े तक के रेट बढ़ाये गये। मंदिरों में वी.आई.पी दर्शन की सुविधा के लिये 1100रू का शुल्क तक लगा दिया। बसों में सामान ले जाने के लिये अतिरिक्त किराया लगाने का फैसला लिया गया। अधिकारियों/कर्मचारियों तक के तबादले नहीं किये गये। ताकि सरकार पर कोई खर्च का बोझ न पड़े। मुख्यमंत्री ने निजी भवनों में चल रहे सरकारी कार्यालय को सरकारी भवनों में शिफ्ट करने के निर्देश दिये ताकि खर्च कम किया जा सके।

ऐसे संकट पूर्ण हालत में सरकार ने यू एस क्लब स्थित पांच सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करने के निर्देश दिये हैं। इन्हें कहा गया है कि वह अपने लिये स्थान का प्रबंध करें। स्वभाविक है कि इन्हें निजी भवनों में ही अपने लिये जगह तलाशनी होगी। शायद पर्यटन विभाग ने तो इन आदेशों की अनुपालना के लिए कदम भी उठा लिए हैं। सरकार के इस आदेश के बाद पहली आशंका तो इस ओर जाती हैं की कहीं यूएस क्लब भी सरकारी रिपोर्टो में अनसेफ भवनों की श्रेणी में तो नहीं आ गया है। जिससे वहां स्थित कार्यालय को दूसरी जगह शिफ्ट करने की आवश्यकता खड़ी हो गयी है। लेकिन सरकार के आदेशों के बाद जो चर्चाएं सामने आयी हैं उनके मुताबिक यू एस क्लब से सरकारी कार्यालयों को शिफ्ट करके वहां पर अधिकारियों के लिए क्लब की व्यवस्था की जायेगी। क्योंकि यह स्थान माल रोड के निकट है और गाड़ियों की पार्किंग आदि की सुविधा भी उपलब्ध है। इस क्लब में अधिकारियों के लिये क्लब बनाने के प्रयास पिछली सरकारों के दौरान भी हुये हैं लेकिन किसी भी मुख्यमंत्री ने ऐसा करने की अनुमति नहीं दी है। जयराम सरकार के समय भी वरिष्ठ अफसरशाही ने ऐसा प्रयास किया था लेकिन मुख्यमंत्री इसके लिये नहीं माने थे।

लेकिन अब आपदा काल में जिस तरह से यह फैसला आया है उससे सरकार की संवेदनशीलता पर गहरे सवाल उठने शुरू हो गये हैं। यह सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे फैसला मंत्री परिषद की बैठक में लिया गया है। क्या मुख्यमंत्री के अपने स्तर पर यह फैसला लिया गया है या अधिकारियों ने अपने स्तर पर ही ऐसा फैसला यह मानकर ले लिया होगा कि मुख्यमंत्री के स्तर पर कोई सवाल नहीं उठाये जाएंगे। वैसे मुख्यमंत्री या उनके सहयोगी किसी भी मंत्री की कोई प्रतिक्रिया नहीं आयी है। आपदा काल में इस तरह के फैसले लिये जाना कठिन वितीय स्थिति और आपदा में सरकारी तंत्र की गंभीरता पर गहरे सवाल छोड़ जाता है। यह चर्चा चल पड़ी है कि सरकार का अफसरशाही पर कोई नियंत्रण नहीं रह गया है। क्योंकि सरकार इस आपदा में हर एक से सहयोग मांग रही है। यदि आम आदमी का सहयोग ऐसे ही कार्यो पर निवेशित होना है तो फिर सहयोग से पहले उसकी पात्रता पर सवाल उठेंगे यह तय है।

आप किसी भी प्रकार की मदद मांगों, केंद्र देगा:नड्डा

शिमला/शैल। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने 20 अगस्त, को भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण हिमाचल प्रदेश में हुए भारी नुकसान का जायजा लिया। उन्होंने प्रदेश में आयी प्राकृतिक त्रासदी में दिवंगत लोगों के परिवारजनों के साथ मुलाक़ात भी की। उन्होंने समरहिल, शिमला में भारी बारिश के कारण हुए ध्वस्त प्राचीन शिव मंदिर स्थल का अवलोकन भी किया और शिमला एवं बिलासपुर में स्थानीय प्रशासन के साथ राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यो पर चर्चा भी की। उनके साथ केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, हिमाचल प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष डॉ राजीव बिंदल भी थे। उन्होंने हिमाचल प्रदेश को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और भारतीय जनता पार्टी की ओर से पूरा सहयोग और समर्थन देने का भरोसा दिया।

हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश, बाढ़ एवं भूस्खलन के कारण आयी तबाही का जायजा लेने और स्थानीय प्रशासन के साथ राहत, बचाव एवं पुनर्वास कार्यो पर चर्चा करने के पश्चात राष्ट्रीय अध्यक्ष ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मैंने आज सिरमौरी ताल एवं कच्ची ढांग में बादल फटने से उत्पन्न हुई स्थिति का जायजा लिया, शिमला

में शिवबावडी और कृष्णा नगर में बाड़ और भारी बारिश क्षेत्रों का दौरा भी किया। आपदा के कारण यहां काफी ग़मगीन माहौल है। हमारी देवभूमि हिमाचल प्रदेश भीषण प्राकृतिक आपदा और त्रासदी के दौर से गुजर रहा है। यहाँ की स्थिति देख कर मेरा हृदय व्यथित और वि}वल है।

नड्डा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश की स्थिति चिंताजनक है और पिछले एक महीने में प्रदेश में भारी नुकसान हुआ है, जिसके बारे में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी भी अवगत हैं और चिंतित हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ही, नितिन गडकरी जी, अनुराग ठाकुर, सभी ने हिमाचल प्रदेश के लिए गंभीरता के साथ कार्य किया है और इस आपदा की घड़ी में पूरी ताकत के साथ संकल्प लेते हुये हिमाचल प्रदेश की मदद की है। उन्होंने कहा कि हमारे सभी सांसद अपना सारा सांसद निधि का पैसा हिमाचल प्रदेश की आपदा के लिए देंगे।

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि संकट की इस घड़ी में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज का विषय मानवता का है, राजनीति का नहीं। हमारा सारा नेतृत्व पूरी ताकत के साथ जनता की सेवा में लगा हुआ है। हमने मुख्यमंत्री, हिमाचल प्रदेश को आश्वासन दिया है कि किसी भी प्रकार की आर्थिक मदद चाहिए तो केंद्र हिमाचल प्रदेश के लिए कोई कमी नहीं रखेगा। केंद्र सरकार हर पहलू पर हिमाचल प्रदेश की मदद करेगी और अगर किसी भी प्रकार की कोई परेशानी आती है तो वे स्वयं मुझे भी बात कर सकते हैं। केंद्र सरकार सड़क, पुनर्वास, भवन पुनर्निर्माण और आम जनजीवन को पटरी पर लाने के लिए पूरी ताकत से कार्य करेगी।

नड्डा ने कहा कि मुख्यमंत्री ने रिलीफ मैनुअल के फंड के बारे में भी हम से चर्चा की है और इस फंड में भी हम किसी भी प्रकार की कमी नहीं आने देंगे। हम बार-बार एक ही चीज कह रहे हैं कि आप हमें समस्या बतायें काम हम करेंगे, आप मदद मांगों केंद्र देगा, आप पैसा मांगों केंद्र देगा। हिमाचल प्रदेश में राज्य आपदा को लेकर टीम आयी थी जो कि अपनी रिपोर्ट केंद्र ले गयी है और हिमाचल प्रदेश के प्रशासन ने भी हमें कई सुझाव दिया है, जिस पर हम कार्य करेंगे।

भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि अभी तक प्रदेश को एसडीआरएफ फंड के तहत 622 करोड़ रुपये का फंड आया है। पीएम ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को लगभग 2700 करोड रुपये प्राप्त हुए हैं। नेशनल हाइवे के साथ-साथ स्टेट हाइवे को भी दुरुस्त करने के लिए भी केंद्र सरकार सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध है। एसडीआरएफ की 20 टीमें, आईटीबीपी की दो टीमें, 3 हेलीकॉप्टर फ़ोर्स हिमाचल के राहत कार्य में सहयोग दे रही हैं। हेलीकॉप्टर के माध्यम से लगभग 1000 से ज्यादा लोगों का जीवन बचाया गया है।

नड्डा ने कहा कि कल हमारी दिल्ली में प्रधानमंत्री के साथ बैठक भी हुई है और उसमें हिमाचल प्रदेश को एसडीआरएफ के तहत 200 करोड़ रुपए की एक और किस्त जारी कर दी गई है, जो कि कल हिमाचल प्रदेश के खाते में पहुंच जाएगी।